डॉ। भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि - भारतीय संविधान के वास्तुकार और देश के पहले कानून और न्याय मंत्री

भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के वास्तुकार और "अछूत" दलित जाति के नागरिक अधिकारों के आजीवन चैंपियन के रूप में जाना जाता है। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और 1952 में मानद उपाधि प्राप्त की। "एक महान समाज सुधारक और मानवाधिकारों के एक महान उत्थानकर्ता। अम्बेडकर महार जाति के थे, जो भारत में अछूत / दलित जातियों में से एक थे। मुंबई में बीए, अंबेडकर ने न्यूयॉर्क (1913-1916) में कोलंबिया विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (1916-1922) से अर्थशास्त्र में मास्टर और डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

अंबेडकर पहले उच्च शिक्षित थे। , हिंदू "अछूत" जाति के राजनीतिक रूप से प्रमुख सदस्य। उन्हें दलित अधिकारों और सामाजिक मान्यता के लिए औपनिवेशिक भारत के एकमात्र स्वायत्त संघर्ष के लिए आज भी याद किया जाता है; जाति जो असमानता और ऐतिहासिक अन्याय के रूप में जाति को दोहराती है; और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए, जिसने उन्हें लोकतांत्रिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई नीति के भारतीय प्रक्षेपवक्र पर गहरा और स्थायी चिह्न छोड़ने की अनुमति दी।

कोलंबिया में एक छात्र के रूप में, डॉ। बीआर अंबेडकर ने इंटरव्यू अमेरिकन उदारवाद के कुछ सबसे बड़े आंकड़े जैसे कि जॉन डेवी और एडवर्ड सेलिगमैन और अमेरिकी इतिहासकार जेम्स शॉटवेल और जेम्स हार्वे रॉबिन्सन के साथ अध्ययन किया। जॉन डेवी, एक अमेरिकी दार्शनिक और शैक्षिक सुधारक, डॉ। अंबेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय के बौद्धिक संरक्षक थे। उनके मार्गदर्शन में, अंबेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपने विचारों के ब्लूप्रिंट तैयार किए।

1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया, "मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं," कोलंबिया में मेरे कुछ सहपाठी और मेरे महान प्रोफेसर थे। "

अपने निकट समकालीन, WEB Du Bois की तरह, अम्बेडकर एक विद्रोही विचारक थे, जिनके लेखन में लगातार यूरोपीय और अमेरिकी इतिहास और राजनीतिक विचार जुड़े। इसने उन्हें राजनीतिक अवधारणाओं की सार्वभौमिकता का पता लगाने की अनुमति दी, साथ ही साथ अन्याय और निर्विवादीकरण के अपने इतिहास के संबंध में यूरो-अमेरिका के अंधेरे इतिहास को उजागर करने के लिए। यह अंबेडकर के विचार-उसकी गहरी वैश्विकता का दोहरा चरित्र है, साथ ही अस्पृश्यता के विशिष्ट संकट के साथ इसकी निरंतर चिंता है जो उसे अपनी पीढ़ी के अन्य एंटीकोलोनियल विचारकों से अलग करती है।

1936 में, अम्बेडकर ने 1936 में उदार हिंदू जाति-सुधारकों के एक समूह की बैठक के लिए अननिहिलेशन ऑफ़ कास्ट लिखा। हालांकि, समूह ने उनके भाषण के मसौदे को देखने के बाद अपना निमंत्रण वापस ले लिया। परिणामस्वरूप, अम्बेडकर ने स्वयं काम प्रकाशित किया, और यह एक त्वरित क्लासिक बन गया। द कोलंबिया सेंटर फॉर न्यू मीडिया टीचिंग एंड लर्निंग उनके काम का एक एनोटेट संस्करण प्रदान करता है जो कि एनीहिलेशन ऑफ कास्ट वेबसाइट पर है। 2004 में कोलंबिया की अपनी 250 वीं वर्षगांठ के जश्न में अपनी वेबसाइट पर अंबेडकर की एक प्रोफ़ाइल शामिल थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2010 के भारत के संसद के अभिभाषण के दौरान स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व के विचारों के आधार पर लोकतांत्रिक न्याय के भारतीय लक्षणों पर अंबेडकर की छाप। राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय संविधान और भारतीय समाज के लिए अंबेडकर के योगदान का आह्वान करते हुए कहा। "हम मानते हैं

कि आप चाहे कोई भी हों या आप कहाँ से आए हों, हर व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पूरा कर सकता है। जिस तरह डॉ। अम्बेडकर जैसे दलित खुद को उठा सकते हैं और संविधान के उन शब्दों को कलमबद्ध कर सकते हैं जो सभी के अधिकारों की रक्षा करते हैं।" भारतीयों का मानना है कि आप चाहे जहाँ रहें - चाहे पंजाब का कोई गाँव हो या चांदनी चौक, कोलकाता का एक पुराना खंड या बैंगलोर में एक नया ऊँचा इलाका हो - हर व्यक्ति सुरक्षा और सम्मान के साथ जीने का एक ही मौका पाने का हकदार है। एक शिक्षा पाने के लिए, काम पाने के लिए, और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने के लिए। ”

अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को सामाजिक संबंधों के संगठन के एक असमान मोड के रूप में देखा, जो शुद्ध और अशुद्ध या तो चरम पर था। उन्होंने तर्क दिया कि इस प्रणाली को धार्मिक संहिताओं के माध्यम से पवित्र किया गया था, जो जातियों के अंतरसंबंधों को रोकती थी और एक विनियमित संरचना तक सामाजिक संपर्क को सीमित करती थी। अंबेडकर अपनी राजनीति और लेखन के माध्यम से दलितों के खिलाफ अत्याचार-विरोधी अधिवक्ता बन गए। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में से एक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जो एक अविभाजित भाषण था, जिसे उन्होंने 1936 में लिखा था।ने

संविधान के पिता

1947 में संविधान सभा की मसौदा समिति की अध्यक्षता करने के लिए चुना था, अम्बेडकर ने विधानसभा में कदम रखते ही अपने कई कट्टरपंथी आरोपों को खारिज कर दिया था। भारत के संविधान के प्रारूपण की प्रक्रिया के माध्यम से। अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक समानता के लिए कुछ विशेष संवैधानिक प्रावधानों में उनके योगदान को देखा जा सकता है (पहली बार अंग्रेजों द्वारा इस्तेमाल किए गए अछूतों के लिए शब्द)। स्वतंत्र भारत के संविधान (अनुच्छेद 15 और 17) में छुआछूत की प्रथा को "समाप्त" कर दिया गया था, और 1955 का अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथाओं को कानून द्वारा दंडनीय बनाता है। अनुच्छेद 46, सकारात्मक कार्रवाई के भारतीय संस्करण को प्रदान करता है, विशेष रूप से समाज के "कमजोर वर्गों" के लिए शैक्षिक और आर्थिक लाभ को बढ़ावा देता है।

अम्बेडकर और गांधी

अम्बेडकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अछूतों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के कारण काफी गंभीर हो गए और 1932 के तथाकथित पूना पैक्ट के परिणाम ने उन्हें एक आलोचक बना दिया। दलितों को लगता है कि गांधी ने उन्हें अलग-अलग मतदाताओं के अधिकार से वंचित कर दिया था, जो उनके लिए वास्तविक राजनीतिक शक्ति थी।

गांधी एक जाति हिंदू, एक वैश्य थे। अंबेडकर एक महार दलित थे और भेदभाव को पहले से जानते थे। गांधी ने कभी भी चार प्रमुख समूहों के वर्ण सिद्धांत का खंडन नहीं किया, हालांकि उन्होंने वर्णों के नीचे एक समूह के विचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्होंने सभी वर्णों को समान माना। अंबेडकर ने पूरी जाति पदानुक्रम को खारिज कर दिया, अछूतों के बीच एक मौजूदा प्रयास को खारिज कर दिया कि “संस्कृतकरण”, यानी अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए उच्च-वर्ग के रीति-रिवाजों को अपनाएं। गांधी अछूतों के अधिकारों के लिए राजनीतिक लड़ाई में विश्वास नहीं करते थे और जब तक मंदिर अधिकारी सहमत नहीं होते, तब तक वे मंदिरों में प्रवेश करने के अपने प्रयासों को मंजूरी देते थे। अम्बेडकर ने महसूस किया कि राजनीतिक शक्ति अस्पृश्यता के समाधान का हिस्सा है। मूल रूप से, गांधी का विश्वास हृदय परिवर्तन में था; अंबेडकर का भरोसा कानून, राजनीतिक शक्ति और शिक्षा में था।